राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 9143/2021

जितेंद्र मीना पुत्र कैलाश चंद मीना, जिनकी आयु लगभग 21 वर्ष है, वीपीओ - नींदरदा, तहसील और जिला सवाईमाधोपुर (राज) के निवासी हैं।

---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस निदेशालय, लाल कोठी, जयपुर।

3. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सह महानिरीक्षक (भर्ती), राजस्थान, जयपुर (राज.)

4. पुलिस अधीक्षक, जीआरपी (उत्तर), जोधपुर (राज.)

---- उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिए :	श्री कैलाश जांगिड़ ए/डब्ल्यू श्री मोहन सिंह शेखावत।
उत्तरदाता(गण) के लिए	: श्री मनीष व्यास, एएजी श्री अनिल बिस्सा,ए.जी. सी.

माननीय डॉ. न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी

<u>निर्णय</u>

रिपोर्टेबल

17/01/2024

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका को निम्नलिखित राहतों का दावा करते हुए प्राथमिकता दी गई है:

> "इसलिए, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि आपका आधिपत्य इस रिट याचिका को स्वीकार करने और अनुमति देने और पूरे रिकॉर्ड को मंगाने और मामले के पूरे रिकॉर्ड की जांच करने और एक उचित रिट, आदेश और निर्देश द्वारा कृपा करने में प्रसन्न हो सकता है:
>
> i) आक्षेपित आदेश दिनांक 09.07.2021 (अनु.5) अवैध घोषित किया गया है और इसे रद्द किया जा सकता है ।
>
> (ii) प्रतिवादी को सभी परिणामी लाभों के साथ जी. आर. पी., जोधपुर में कांस्टेबल जी. डी. के पद पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने का निर्देश दिया जा सकता है।
>
> (iii) कोई अन्य आदेश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित समझता है, याचिकाकर्ताकर्ता के पक्ष में भी पारित किया जा सकता है।"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखे गए मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए कांस्टेबल के पद के लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के तहत दिनांक 04.12.2019 को विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता ने, पात्र होने के नाते, उक्त विज्ञापन के अनुसरण में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने परीक्षा में भाग लिया और उसे उसी में सफल घोषित किया गया। प्रतिवादी ने 10.04.2021 पर प्रेस नोट जारी किया, जिसमें वर्तमान याचिकाकर्ता सहित सफल उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया। इसके बाद, प्रतिवादी ने विचाराधीन पद के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 22 में दिखाया गया था।

2.1. इसके बाद, प्रतिवादी ने दिनांक 09.07.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के कारण विचाराधीन पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इस प्रकार, उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, पूर्व उद्धृत राहतों का दावा करने वाली वर्तमान याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था; हालाँकि, उस समय जब याचिकाकर्ता किशोर था, एक प्राथमिकी जिसमें सं. 250/2018 उसके और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन, सूरवाल, जिला सवाईमाधोपुर में दर्ज की गयी थी, लेकिन याचिकाकर्ता एक किशोर होने के कारण, प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता के मामले की सुनवाई, भा.दं.सं. की धारा 341, 323, 452 और 34 के तहत अपराध के लिए विद्वान किशोर न्यायाधीश बोर्ड (जेजेबी), सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई थी।

3.1.विद्वान वकील ने आगे कहा कि विद्वान जेजेबी ने अपने आदेश दिनांक 05.08.2019 में याचिकाकर्ता की स्वीकारोक्ति पर विचार किया और 700/- रुपये के जुर्माने के निर्देश के साथ उसे दोषी ठहराया और इसके अलावा, विद्वान जेजेबी ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 24 के अनुसार, याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में अयोग्यता के रूप में ऐसी सजा को हटाने के लिए एक टिप्पणी की।

(इसके बाद '2015 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित)।

3.2. विद्वान वकील का यह भी कहना है कि विद्वान जेजेबी द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता को विवादित आदेश में बताए गए कारण के आधार पर, प्रश्नगत पद के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था; इसके अलावा, समय बीतने के साथ और उपरोक्त एफआईआर में मुख्य आरोपी और अन्य सह-अभियुक्तों को बरी करने पर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर द्वारा, दिनांक 26.07.2019 के फैसले के तहत, प्रश्न में अयोग्यता अब नहीं बची है।

3.3.विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक मेधावी उम्मीदवार है और प्रश्नगत पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद चुना गया था, और इसलिए, उपरोक्त कारणों के आधार पर, याचिकाकर्ता को केवल उपरोक्त आपराधिक मामले के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता था।

3.4 इस तरह की प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा कियाः-

*(*क*)* राजस्थान राज्य और अन्य बनाम सुश्री सज्जना *(*डी.बी.विशेष अपील याचिका संख्या *684/2022,* निर्णय *12.07.2022)* इस माननीय न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित*;*

*(*बी*)* सुश्री सज्जना बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य *(*एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी.*)* संख्या *10818/2021, 09.12.2021* को निर्णय लिया गया*)* इस माननीय न्यायालय की एक समन्वित पीठ द्वारा पारित किया गया।

4. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से किए गए उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि आवेदन पत्र जमा करने के समय, याचिकाकर्ता ने कॉलम में "नहीं" प्रस्तुत किया अर्थात क्या उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है; इसलिए, भौतिक तथ्य को छिपाने के आधार पर, विवादित आदेश के माध्यम से विचाराधीन पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को सही ढंग से खारिज कर दिया गया था।

4.1. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों के सत्यापन के समय भी आपराधिक मामला दर्ज करने के तथ्य का खुलासा नहीं किया। विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करते हैं कि परिपत्र सं. 1300 पुलिस महानिदेशक, राजस्थान के कार्यालय द्वारा जारी दिनांकित 28.03.2017, याचिकाकर्ता का मामला विभागीय समिति द्वारा विचार के लिए मुख्यालय को भेजा गया था, जिसके बाद, यह निर्णय लिया गया था, दिनांकित 09.07.2021 के आदेश के अनुसार, कि याचिकाकर्ता विचाराधीन पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, और ठीक ही है।

4.2. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार, प्रतिवादी-विभाग को संबंधित उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है, और उसके बाद, तदनुसार एक निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है। विद्वान वकील का यह भी कहना है कि याचिकाकर्ता को दिए गए 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ, उसे प्रश्नगत पद के लिए पात्र नहीं बनाएगा। विद्वान वकील के अनुसार, याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया में आपराधिक मामले के संबंध में इच्छापूर्वक और जानबूझकर महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है, और इसलिए, विवादित आदेश कानून में उचित है।

4.3. इस तरह की प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान वकील ने महेंद्र सिंह सिसौदिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में इस माननीय न्यायालय की एक

समन्वित पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया। (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 11769/2021, निर्णय 28.09.2022) .

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और साथ ही बार में उद्धृत निर्णयों के साथ मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

6. यह न्यायालय देखता है कि प्रतिवादी ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए कांस्टेबल के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता, पात्र होने के नाते, उक्त विज्ञापन के अनुसरण में विचाराधीन पद के लिए अपना आवेदन पत्र जमा किया, कॉलम में "नहीं" जमा करते हुए, क्या उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके बाद, याचिकाकर्ता को, विचाराधीन भर्ती प्रक्रिया में उसकी भागीदारी पर, सफल घोषित किया गया, और संबंधित अधिकारियों के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए भी उपस्थित हुआ। इसके बाद प्रश्नगत पद के लिए उत्तरदाताओं द्वारा जारी की गई चयन सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल था। इसके बाद, प्रतिवादी ने दिनांक 09.07.2021 के विवादित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के कारण विचाराधीन पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

7. यह न्यायालय आगे मानता है कि इस मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 22.07.2021 का एक अंतरिम आदेश लागू है; इसे नीचे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> “नोटिस जारी करें। स्थगन आवेदन की सूचना भी जारी करें, जो छह सप्ताह के भीतर वापस की जा सकती है।
>
> इस बीच, याचिकाकर्ता के चयन/नियुक्ति के रद्द होने के कारण खाली होने वाले पद को नहीं भरा जाएगा।”

8. इस मोड़ पर, यह न्यायालय भारत संघ बनाम रमेश बिश्नोई, (2019) 19 एस. सी. सी. 710 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रासंगिक भागों को पुनः प्रस्तुत करना उचित समझता है।

> *“8.* तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जिस समय प्रतिवादी के खिलाफ आरोप तय किए गए थे, उस समय *30-6-2009* पर प्रतिवादी की आयु *18* वर्ष से कम थी क्योंकि उसकी जन्म तिथि *5-9-1991* है। सबसे पहले, यह विवादित नहीं था कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप कभी साबित नहीं हुए क्योंकि लड़की और उसके माता-पिता ने प्रतिवादी के खिलाफ गवाही नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप *24-11-2011* को उसे बरी कर दिया गया। भले ही आरोप सही पाए गए हों, फिर भी

प्रतिवादी को ऐसे आरोपों के आधार पर नौकरी पाने से वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि वही आरोप तब लगाए गए थे जब प्रतिवादी नाबालिग था। **कानून यानी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, *2000* के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, *2015* का जोर यह है कि अगर किसी किशोर को दोषी ठहराया जाता है, तो भी उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, ताकि किशोर के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी अपराध के संबंध में कोई कलंक न लगे। इसका स्पष्ट उद्देश्य ऐसे किशोरों को बिना किसी कलंक के एक सामान्य व्यक्ति के रूप में समाज में पुनः शामिल करना है।**

8.1. **राजस्थान राज्य बनाम भवानी शंकर मूर 2023 एससीसी ऑनलाइन राज 381** के मामले में इस माननीय न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले के प्रासंगिक अंश भी यहां दिए गए हैं:

"7. जो भी हो सकता है। 2015 के अधिनियम की धारा 24 की भाषा और 2000 के अधिनियम में संबंधित प्रावधान, यानी धारा 19 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि संघर्ष में बच्चे को दोषी ठहराए जाने के रिकॉर्ड को संरक्षित नहीं किया जा सकता है और इसे नष्ट किया जाना चाहिए। **प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, दोषसिद्धि से संबंधित किसी भी अयोग्यता को नजरअंदाज करना होगा और किसी भी तरह से कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के नुकसान के लिए कार्य नहीं किया जा सकता है, जिसमें सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया शामिल होगी।**

8. नतीजतन, ऐसी स्थिति में, **नियोक्ता को कानून द्वारा दोषसिद्धि के निर्णय का उल्लेख करने या उस पर विचार करने से प्रतिबंधित किया जाता है ताकि एक सफल उम्मीदवार, जो किसी समय कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चा था, को सरकारी सेवा में नियोजित होने से वंचित किया जा सके। विद्वान एकल पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जिसके तहत दिनांक *18.12.2018* के आदेश द्वारा प्रतिवादी की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया था, को अमान्य घोषित कर दिया गया था, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कोई दुर्बलता नहीं है।"**

9. इस अदालत ने आगे कहा कि उपरोक्त प्राथमिकी याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज की गई थी और उक्त मामले की सुनवाई विद्वान किशोर न्यायाधीश बोर्ड (जेजेबी) द्वारा की गई थी क्योंकि याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर एक किशोर था; याचिकाकर्ता

द्वारा स्वीकारोक्ति आवेदन दायर किए जाने पर, विद्वान जेजेबी ने याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया और 05.08.2019 के बयान के लिए निर्देश दिया-और याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में 2015 के अधिनियम की धारा 24 के अनुसार अयोग्यता को हटाने के संबंध में भी टिप्पणी की। उक्त धारा 24 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> **"*24.* अपराध के निष्कर्ष पर अयोग्यता को हटाना। –**
>
> *(1)* उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक बच्चा जिसने कोई अपराध किया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निपटा गया है, वह ऐसे कानून के तहत अपराध की सजा से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, का सामना नहीं करेगाः
>
> बशर्ते कि ऐसे बच्चे के मामले में जो सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है और बाल न्यायालय द्वारा धारा *19* की उप-खंड *(1)* के धारा *(i)* के तहत कानून के साथ टकराव में पाया जाता है, उप-धारा *(1)* के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
>
> *(2)* बोर्ड पुलिस को, या बाल न्यायालय द्वारा अपनी रजिस्ट्री को निर्देश देते हुए एक आदेश देगा कि ऐसी सजा के प्रासंगिक रिकॉर्ड अपील की अवधि की समाप्ति के बाद नष्ट कर दिए जाएंगे, जैसा भी मामला हो, एक उचित अवधि जो निर्धारित की जा सकती है*:*
>
> बशर्ते कि किसी जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चा धारा *19* की उपधारा *(1)* के खंड *(i)* के तहत कानून के उल्लंघन में पाया जाता है, ऐसे बच्चे की सजा के प्रासंगिक रिकॉर्ड बाल न्यायालय द्वारा बनाए रखे जाएंगे।*"*

9.1. यह न्यायालय यह भी देखता है कि विद्वान जेजेबी ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि दोषसिद्धि आदेश, उसमें की गई टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में किसी भी तरह से अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा और माना जाएगा।

दिनांकित 05.08.2019 आदेश के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

> " साथ ही यह आदेश भी दिया जाता है कि किशोर जितेंद्र के विरुद्ध की गयी उक्त दोषसिद्धि धारा *24* किशोर न्याय अधिनियम के तहत वाद गुजरने मियाद अपील किशोर किसी भी दोषसिद्धि कि निर्हरता

से ग्रसित नहीं होगा। अर्थात किशोर इस प्रकरण कि वजह से पढ़ाई, नौकरी या अन्य व्यवसाय हेतु अयोग्य करार नहीं दिया जावे इस दोषसिद्धि के अभिलेख को भी रिकॉर्ड से हटा दिया जावे इस दोषसिद्धि का किशोर के भविष्य पर प्रभाव गुजरने मियाद अपील शून्य समझा जावे। "

10. यह न्यायालय आगे देखता है कि विद्वान जेजेबी के उपरोक्त आदेश में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की गणना पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा, और इसलिए, याचिकाकर्ता ने मामले के उस दृष्टिकोण में, प्रश्न के संबंध में आवेदन पत्र के कॉलम में "नहीं" का उल्लेख किया है कि क्या उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जो आवेदन पत्र में प्रकटीकरण, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, कानून में उचित है।

11. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता को संबंधित जेजेबी द्वारा 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ दिया गया था, यह आदेश देते हुए कि दोषसिद्धि को सेवा की संभावनाओं आदि सहित भविष्य की किसी भी संभावना के संबंध में अयोग्यता के रूप में नहीं माना जाएगा और इस तरह की दोषसिद्धि के रिकॉर्ड को भी समाप्त करने का आदेश दिया गया था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को कानून के उपरोक्त प्रावधान के तहत दोषी ठहराया गया था, जो कि इतनी जघन्य प्रकृति का नहीं है, और अपराध करने के समय, याचिकाकर्ता नाबालिग था, और इसलिए, याचिकाकर्ता को उसकी दोषसिद्धि के आधार पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान जेजेबी द्वारा पारित आदेश के आलोक में, नियुक्ति, परीक्षा और किसी अन्य सार्वजनिक रोजगार के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

12. यह न्यायालय देखता है कि 2015 के अधिनियम की धारा 3 (xiv) वाले अध्याय 2 में, यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, किशोर अपराध के सभी पिछले अभिलेखों को मिटा दिया जाएगा, और इस प्रकार, इस तरह के प्रावधान को शामिल करते समय विधायिका का इरादा इस प्रभाव के लिए काफी साफ़ और स्पष्ट था कि किशोर के पिछले आचरण को किशोर की भविष्य की संभावनाओं के संबंध में एक बाधा नहीं माना जा सकता है, और उसी के लिए, 2015 के अधिनियम की धारा 24 के लाभ देने

के लिए एक प्रावधान किया गया है। द्वितीय अध्याय के प्रासंगिक भाग को नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

"अध्याय *II* बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत

धारा *3-(xiv)* नई शुरुआत का सिद्धांतः विशेष परिस्थितियों को छोड़कर किशोर न्याय प्रणाली के तहत किसी भी बच्चे के सभी पिछले रिकॉर्ड मिटा दिए जाने चाहिए।

"

12.1. यह न्यायालय आगे देखता है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 14 में भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि किशोर की सजा से संबंधित रिकॉर्ड अपील की अवधि समाप्ति के बाद नष्ट कर दिया जाएगा।

उक्त नियम 14 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

***"14.* अभिलेखों का विनाश** - कानून के साथ टकराव में एक बच्चे के संबंध में दोषसिद्धि के रिकॉर्ड को अपील की अवधि समाप्त होने तक या सात साल की अवधि के लिए सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा, और उसके बाद प्रभारी व्यक्ति या बोर्ड या बाल न्यायालय द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो सकता हैः

बशर्ते कि एक जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चा अधिनियम की धारा *19* की उप-धारा *(1)* के खंड *(i)* के तहत कानून के साथ संघर्ष में पाया जाता है, ऐसे बच्चे की दोषसिद्धि के प्रासंगिक रिकॉर्ड बाल न्यायालय द्वारा रखे जाएंगे।"

12.2. इस न्यायाधीश ने आगे कहा कि 2015 के अधिनियम की धारा 3 (xiv) और 24 के साथ-साथ किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 14 को लागू करने के पीछे विधायिका का इरादा किशोर को दोषसिद्धि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और संबंधित किशोर की भविष्य की संभावनाओं के लिए अयोग्यता के रूप में उक्त दोषसिद्धि को हटाना है। यह न्यायालय यह भी देखता है कि इस तरह के अधिनियमन के पीछे विधायी इरादा स्पष्ट है कि यदि किशोर को

अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और संबंधित न्यायालय/बोर्ड के पास अयोग्यता को हटाकर 2015 के अधिनियम की धारा 24 के लाभों को बढ़ाने का विकल्प है, इस तथ्य के साथ कि उक्त खंड की भाषा में भी इस तरह के दोषसिद्धि रिकॉर्ड को नष्ट करने की आवश्यकता है। 2015 के अधिनियम की धारा 24 के ऐसे लाभों को बढ़ाने के बाद, तत्कालीन संबंधित किशोर को किसी भी सरकारी विभाग आदि और/या सार्वजनिक रोजगार में किसी भी अन्य संभावनाओं में भविष्य में किसी भी रोजगार के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

13. यह न्यायालय 'विस्मृत होने के अधिकार' के प्रति सचेत है जिसे दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **जोरावर सिंह मुंडी @जोरावर सिंह मुंडी अन्य बनाम भारत संघ और अन्य *(डब्ल्यूपी (सी) 3981/2021)*** के मामले में पारित दिनांक 12.04.2021 के आदेश में संदर्भित और निपटाया गया है।

13.1. **जोरावर सिंह मुंडी @ जोरावर सिंह मुंडी (उपरोक्त)** के मामले में उल्लिखित 'विस्मृत होने के अधिकार' के साथ-साथ 2015 के अधिनियम की धारा 3 (xiv) और 24 के साथ-साथ किशोर न्यायाधीश (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के नियम 14 के अधिनियमन पर संयुक्त रूप से विचार करते हुए, इस अदालत ने कहा कि किशोर अपराध के मामलों में, यदि किसी किशोर के किसी भी आपराधिक पूर्व रिकॉर्ड को बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, तो प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके, यह न केवल किशोर के लिए अवमान और अपमान ला सकता है, बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ किशोर की भविष्य की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

13.2. यह न्यायालय व्यापक 'विस्मृत होने के अधिकार' के दायरे में प्रवेश नहीं करना चाहता है, लेकिन वर्तमान में, विशेष रूप से 2015 के अधिनियम की खंड 24 के परिप्रेक्ष्य में एक किशोर के लिए 'विस्मृत होने के अधिकार' को ऐसे किशोर की भविष्य की संभावनाओं की सुरक्षा के लिए एक आत्यन्तिक अधिकार के रूप में विचार कर रहा है।

13.3. इस तरह का खुलासा न केवल एक किशोर के 'भूल जाने के अधिकार' को प्रभावित करेगा, बल्कि 2015 के अधिनियम को लागू करने और उसमें धारा 24 को शामिल करने के पीछे विधायिका के उद्देश्य और इरादे को भी विफल कर देगा।ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर, 2015 के अधिनियम के विधायी इरादे को भी विफल कर दिया जाएगा, विशेष रूप से, भविष्य के रोजगार और एक किशोर की समान

संभावनाओं के संबंध में, क्योंकि इस तरह, किशोर के पुनर्वास और उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे किशोर फिर से आपराधिक अपराध का सहारा ले सकता है। यह तब अधिक होता है जब वर्तमान समय के विकासशील समाज अपनी जटिलता में गतिशील और आत्म-व्याख्यात्मक होते हैं और उसके बाद कभी न खत्म होने वाले परिवर्तन होते हैं, और किशोर इसके लिए कोई अपवाद नहीं है, बल्कि बहुत अधिक कमजोर होता है, क्योंकि उसके (किशोर) पिछले जीवन की नकारात्मकता, 2015 के अधिनियम जैसे बहुत मजबूत कानून के अधिनियमन के बावजूद, जिसका विधायी इरादा रिकॉर्ड से उसके आपराधिक पूर्ववृत्त को हटाना है, बल्कि उसके पूरे रिकॉर्ड को नष्ट करना है, अगर इसे बनाए रखने और बरकरार रखने की अनुमति दी जाती है, तो इसे अनजान कारणों से, किशोर के कल्याण और भविष्य के कल्याण के खिलाफ फिर से देखा जाएगा, जिससे किशोर को भविष्य में शर्मिंदगी होगी।

13.4.अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की खंड 12 'दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता को हटाने' की बात करती है, लेकिन 2015 के अधिनियम की धारा 24 में प्रयुक्त भाषा न केवल आपराधिक पूर्ववृत्त को हटाने या मिटाने के लिए है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर एक प्रावधान निर्धारित करती है कि एक किशोर के आपराधिक पूर्ववृत्त को पूरी तरह से मिटा दिया जाए/नष्ट कर दिया जाए, ताकि एक किशोर की ऐसी पिछली दोषसिद्धि या आपराधिक अपराध को आगे नहीं बढ़ाया जा सके, ताकि उसकी भविष्य की संभावनाओं पर उसके पिछले अपराध के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।

14. अब उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा अपने किशोर अपराध और दोषसिद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत न करने को कानून के तहत एक वैध बहाने के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और अतीत/पिछले आपराधिक अपराध की ऐसी पिछली नकारात्मकता का उपयोग वर्तमान याचिकाकर्ता की तरह पदधारी को नुकसान पहुंचाने के लिए करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि उसे यहां शामिल भर्ती अभ्यास से बाहर किया जा सके, जिससे 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ दिए जाने के बावजूद याचिकाकर्ता के करियर की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

15. इस न्यायालय ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में एक बार उपरोक्त 2015 के अधिनियम की धारा 24 के पीछे स्पष्ट विधायी इरादे को देखते हुए, विद्वान जेजेबी ने हालांकि याचिकाकर्ता को अपराध के लिए दोषी ठहराया है, लेकिन आदेश दिया है कि इसे याचिकाकर्ता की किसी भी भविष्य की संभावना के संबंध में अयोग्यता के रूप

में नहीं माना जाएगा और यह भी आदेश दिया है कि दोषसिद्धि का पूरा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाएगा, फिर वर्तमान याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि, 2015 के अधिनियम की धारा 24 के निर्देशों के आलोक में, याचिकाकर्ता को किसी भी भर्ती या अन्य भविष्य की संभावनाओं के लिए हकदार बनाने के लिए एक बाधा के रूप में नहीं माना जा सकता है, जिसमें इस मामले में शामिल व्यक्ति भी शामिल है।

16. यह न्यायालय यह भी देखता है कि याचिकाकर्ता एक मेधावी उम्मीदवार है और विचाराधीन पद के लिए भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पारित कर चुका है, और एक बार सक्षम न्यायालय, जिसने याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले की सुनवाई की, ने 2015 के अधिनियम की धारा 24 का आह्वान करते हुए एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि उक्त दोषसिद्धि आदेश याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है, और इसलिए, याचिकाकर्ता को विचाराधीन आपराधिक मामले में दोषसिद्धि की गिनती पर प्रश्नगत पद के लिए अयोग्य/अयोग्य घोषित करने वाले विवादित आदेश को कानून की नजर में कायम नहीं रखा जा सकता है।

17. प्रतिवादी की ओर से उद्धृत निर्णय भी उनके मामले में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वे किशोर अपराध से संबंधित नहीं हैं।

18. इस प्रकार यह न्यायालय मानता है कि एक बार जब 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाता है, जो प्रासंगिक समय पर एक किशोर था, तो उस मामले में, भले ही भर्ती प्रक्रिया के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन दोषसिद्धि की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई थी, उसे उसकी ओर से 'छिपाना' नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते हुए और उसे कानूनी प्रावधान का उपरोक्त लाभ देते हुए, विद्वान जेजेबी द्वारा आदेश दिए गए दोषसिद्धि रिकॉर्ड को मिटाना/नष्ट करना, याचिकाकर्ता की भविष्य की संभावनाओं पर इस तरह के दोषसिद्धि के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए था।

19. इस न्यायालय ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि एक किशोर के संबंध में 'विस्मृत होने का अधिकार', जहां 2015 के अधिनियम की धारा 24 एक निश्चित अधिकार बना रहेगा और एक किशोर, जिसे धारा 24 का लाभ दिया गया है, उसे कहीं भी अभिलेख पर नहीं रखकर अपने किशोर अपराध को मिटाने का हकदार होगा, क्योंकि इस तरह के अभिलेख का निर्माण या निरंतरता, किशोर के लिए एक प्रकार की शर्मिंदगी को उजागर कर सकती है, जिसका निश्चित रूप से उसकी भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसमें सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन प्रक्रिया शामिल है, और किशोर कानूनों के विधायी इरादे के खिलाफ जाता है।

20. यह न्यायालय निर्देश देता है कि किशोर अपराध के अभिलेख को हटाकर/नष्ट करके किशोर के लिए 'भूल जाने का अधिकार' एक आत्यन्तिक अधिकार है, और इसलिए, इसे पूरा अर्थ देने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिकल्पित 'राज्य' की परिभाषा के तहत आने वाले राज्य के साथ-साथ अन्य निकायों को कानूनी रूप से भविष्य में, तत्कालीन किशोर से उसके किशोर अपराध के पिछले रिकॉर्ड/जानकारी के बारे में कोई भी जानकारी मांगने से प्रतिबंधित किया जाता है, उन मामलों में जहां 2015 के अधिनियम की धारा 24 का लाभ दिया गया है, ताकि किशोर की भविष्य की संभावनाओं पर इस तरह के अपराध के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।

21. इस प्रकार, उपरोक्त टिप्पणियों के प्रकाश में और वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है, और दिनांक 09.07.2021 (अनुबंध-5) के आक्षेपित आदेश को रद्द और अपास्त करते हुए, उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है उपरोक्त आपराधिक मामले पर विचार न करने और आपराधिक मामले की जानकारी न देने को किशोर (याचिकाकर्ता) के खिलाफ प्रश्नगत पद पर भर्ती के लिए अयोग्यता/अयोग्यता के रूप में न दे।प्रतिवादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को उस पद पर नियुक्ति दें, यदि वह अन्यथा पात्र है और योग्यता में आता है। सभी लाभ याचिकाकर्ता को संभावित रूप से प्राप्त होंगे। सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है।

(डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।